# पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

## भारत सरकार का एक उपक्रम

## पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

## "क्यू4 और वित्त वर्ष 2013-14 के परिणाम"

## निवेशकों का सम्मेलन : सम्मेलन कक्ष, बीएसई,मुंबई

**दिनांक : 28 मई, 2014**

**समय : सांय 4.00 बजे**

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

**<u>संचालक</u> :** भाइयो और बहनो, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कन्सेप्ट पब्लिक रिलेशन्स से मैं, उनेज़ा शेख पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के निवेशक सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए, कंपनी के क्यू4 और वित्त वर्ष 2013-14 के परिणामों की घोषणा करता हूं और

आपको कंपनी के आगामी कार्यकलापों से अवगत कराता हूं। इस सम्मेलन के मंच पर विराजमान उच्चाधिकारियों में, श्री एम.के. गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड मंच के मध्य भाग में विराजमान हैं। उनके दाहिनी ओर श्री आर.नागराजन, निदेशक (वित्त), उनके दाहिनी ओर श्री जे.एन. प्रसन्न कुमार, स्वतंत्र निदेशक, उनके दाहिनी ओर श्री योगेश चन्द्र गर्ग, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के बाईं ओर श्री ए.के. अग्रवाल, निदेशक (परियोजना), उनके बाईं ओर श्री सुभाषचन्द्र, मुख्य सतर्कता अधिकारी विराजमान हैं। अब मैं श्री एम. के. गोयल जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हमें क्यू4 और वित्त वर्ष 2013-14 की निष्पादन संबंधी मुख्य विशेषताओं से अवगत कराएं।

**<u>एम. के. गोयल</u> :** नमस्कार। पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड की निष्पादन संबंधी मुख्य विशेषताओं को साझा करने के लिए इस

निवेशक सम्मेलन में पधारे आप सभी का स्वागत है। क्यू4 और क्यू4 और वित्त वर्ष 2013-14 के वित्तीय परिणाम आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

क्यू4 और वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान चुनौतीपूर्ण आर्थिक वातावरण के बावजूद, इस वर्ष में हमारा निष्पादन उत्साहवर्धक रहा है। इस वर्ष, हमने अपनी बही में अच्छा परिसंपत्ति विकास कर और अच्छे मार्जिन प्राप्त कर अच्छी लाभप्रदता दर्शाई है। इसक साथ

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

ही साथ, हमने अपनी परिसंपत्तियों की गुणता भी बनाए रखी है और अनुत्पादक परिसंपत्तियों का स्तर भी अपेक्षाकृत निम्न रहा है। हमारी पूंजीगत पर्याप्तता का अनुपात 20 प्रतिशत से अधिक रहा है, जो यह दर्शाता है कि निकट-सावधि विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

हमारा यह उत्साहवर्धक निष्पादन हमारे व्यावसायिक मॉडल के दमदार होने का द्योतक है और यह हमारी इस योग्यता को दर्शाता है कि हम भारत के विद्युत क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों का समाना प्रभावी ढंग से कर सकते हैं।

हमारे इस वर्ष के कर पश्चात लाभ में 23 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। यह कर पश्चात लाभ पहले 4,420 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 5,418 करोड़ रुपए हो गया है। हमारी ऋण संबंधी परिसंपत्तियों में 18 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। ऋण संबंधी परिसंपत्तियों की यह वृद्धि पहले 1,60,000 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 1,90,000 करोड़ रुपए (लगभग), हो गई है। तथापि, यदि हम परिसंपत्ति संबंधी मानक व्यवस्था, पूर्व हानि, आदि जैसी असाधारण मदों को हटा दें, तो हमारा कर पश्चात लाभ वास्तव में 31 प्रतिशत से भी अधिक है, क्योंकि यह कर पश्चात लाभ पहले 4682 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 6,141 करोड़ रुपए हो गया है।

आपको यह विदित होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों का पालन करते हुए, हमने वित्त वर्ष 2013-14 से तक वित्त वर्ष 2014-15 तक परिसंपत्ति संबंधी मानक व्यवस्था 0.25 प्रतिशत की दर से किए जाने की पहल एक चरणबद्ध तरीके से की है।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

लेकिन, वित्त वर्ष 2013-14 में अपनी उच्चतर लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए, हमने यह निर्णय किया है कि क्यू4 वित्त वर्ष 2012-13 में ही 0.25 प्रतिशत की शेष संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। इसके परिणामस्वरूप, क्यू4 वित्त वर्ष 2013-14 में, हमारे कर पश्चात लाभ में क्यू $_0$क्यू आधार पर केवल 9 प्रतिशत तक की ही वृद्धि हुई है। लेकिन, यदि हम क्यू4 की उन असाधारण मदों को हटा दें, जिनका उल्लेख वित्तीय वर्ष के लाभों के संबंध में पहले किया गया है, तो क्यू4 के कर पश्चात लाभ में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि

हुई है, क्योंकि क्यू4 का यह कर पश्चात लाभ क्यू4 वित्त वर्ष 2013 में 1,320 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 1,655 करोड़ रुपए हो गया है। इसके फलस्वरूप, परिसंपत्ति संबंधी जो कुल मानक व्यवस्था वित्त वर्ष 2013 में 133 करोड़ रुपए थी, वह अब वित्त वर्ष 2013 - 14 में बढ़कर 337 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। परिसंपत्ति संबंधी जो संपूर्ण व्यवस्था भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में की जानी अपेक्षित थी, उसे पूर्व-परिसंपत्तियों के संबंध में पहले ही कर लिया गया है।

अस्थिर ब्याज दरों और फोरेक्स बाजारों के बावजूद, हमने अपनी उधार लागतों को इस वर्ष में प्रतिस्पर्धा बनाए रखा है। हमने इस वर्ष में 8.96 प्रतिशत की सीमांत लागत पर लगभग 450000 करोड़ रुपए की

बढ़ोत्तरी की है, जबकि इस सीमांत लागत में कर- मुक्त बंधपत्रों की 5000 करोड़ रुपए की राशि भी सम्मिलत है।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष में औसत उत्पादन से उच्च दरों से नए संवितरण भी किए गए थे। हमने अपनी ऋण संबंधी मौजूदा परिसंपत्तियों का उच्चतर दरों से पुन- मूल्य निर्धारण किया था, जिसके कारण हमने 144 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय भी की थी। इसके परिणामस्वरूप, ब्याज की सीमा में 59 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है, क्योंकि ब्याज की यह सीमा 2.86 प्रतिशत से बढ़कर 3.45 प्रतिशत हो गई है। तदनुसार, इस वर्ष के दौरान हमारे ब्याज की निवल आय में इस वर्ष में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 6,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 8500 करोड़ रुपए (लगभग), हो गई है।

जहां तक अनुत्पादक परिसंपत्तियों का संबंध है, हालांकि इस उद्योग ने अनुत्पादक परिसंपत्तियों में वृद्धि होने की प्रवृत्तियां दर्शाई थीं, फिर भी हम अनुत्पादक परिसंपत्तियों के अनुपातों का स्तर निम्न बनाए रखने में समर्थ हुए हैं। दिनांक 31.03.2014 को हमारी सकल अनुत्पादक परिसंपत्तियों के स्तरों में गिरावट आई है, क्योंकि ये स्तर पिछले वर्ष 0.71 प्रतिशत थे, जो अब घटकर 0.65 प्रतिशत हो गए हैं। साथ ही हमारी निवल अनुत्पादक परिसंपत्तियों में भी कमी आई है, क्योंकि हमारी निवल अनुत्पादक परिसंपत्तियां पिछले वर्ष 0.63 प्रतिशत थीं, जो अब घटकर 0.52 प्रतिशत हो गई हैं। हमने क्यू4 वित्त वर्ष 2013-14 में किसी भी ऋण का पुनर्गठन नहीं किया है। लेकिन,क्यू4 वित्त वर्ष 2013 में केवल एक लघु लेखा का वर्गीकरण अनुत्पादक परिसंपत्ति के रूप में किया गया है, कृष्णा-गोदावरी पावर लिमिटेड के नाम 77 करोड़ रुपए मात्र का ऋण बकाया है, जिसके लिए

8 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। दिनांक 31-03-2014 को हमारी सकल अनुत्पादक परिसंपत्तियां 1,228 करोड़ रुपए की हैं और निवल अनुत्पादक परिसंपत्तियां 985 करोड़ की हैं, जबकि ऋण संबंधी परिसंपत्तियां लगभग 1,90,000 करोड़ रुपए की हैं, जो

ऋण संबंधी बही की 0.5 प्रतिशत मात्र है वित्त वर्ष 2013-14 में , हमने 88 प्रतिशत अंतरिम लाभांश घोषित किया है, जो पिछले वर्ष में घोषित लाभांश का लगभग 1.5 गुना है।

कल बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमने 2 प्रतिशत अतिरिक्त अंतिम लाभांश का अनुमोदन किया है और उसके द्वारा हमने इस वर्ष के लिए कुल 90 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की है।

जहां तक पूंजीगत पर्याप्तता से संबंधित अपेक्षा का संबंध है, हमारी पूंजीगत पर्याप्तता में दिनांक 31-03-2013 को 17-64 प्रतिशत मात्र थी, और इसका मुख्य कारण यह है कि चालू वर्ष में 3800 करोड़ रुपए की राशि के गौण ऋणों सबॉर्डिनेटिड लोनों में बहुत ही प्रतिस्पर्धी दरों से वृद्धि हुई है। मैं, आप सभी के ध्यान मे यह लाना चाहूंगा कि दीर्घकालिक प्रधान ऋणों सीनियर लोनों में जिन दरों से वृद्धि हुई थी, हम लगभग उन्हीं दरों से गौण ऋणों में हुई इस वृद्धि का एक अतिरिक्त लाभ हैं और वह यह है कि उनसे हमारी पूंजीगत पर्याप्तता के अनुपात में बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए, हम न्यूनतम 15 प्रतिशत की

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

नियामक अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, अपनी पूंजीगत पर्याप्तता के प्रति बहुत ही निश्चिंत हैं।

जहां तक हमारे व्यावसायिक निष्पादन का संबंध है, किफ़ायत के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय विद्युत क्षेत्र वित्त वर्ष 2013-14 में बहुत सी प्रतिकूलताओं का सामना कर रहा है, विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और हम अपने व्यासायिक

सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। हमने 59000 करोड़ रुपए के अपने लक्ष्य की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 में (लगभग), 61,000 करोड़ रुपए की ऋण मंजूरियां प्राप्त की हैं। जो परिवर्तनशील ऋण (ट्रांजीशन लोन) किसी प्रयोजन-विशेष के लिए थे, यदि हम उन्हें सम्मिलित न करें, तो पिछले वर्ष की तुलना में हमारी ऋण मंजूरियां लगभग उसी स्तर की रही हैं, जिनकी राशि लगभग 56,000 करोड़ रुपए है।

जहां तक संवितरण का संबंध है, पिछले वर्ष 4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए, हमने वित्त वर्ष 2013-14 में अपने 47,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 47,162 करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया है। लेकिन, यदि हम उन परिवर्तनशील ऋणों को सम्मिलित न करें, जो किसी प्रयोजन- विशेष के लिए थे, तो हमारे ऋण संबंधी संवितरणों में, इस वर्ष में वास्तव में 23 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हुई है, क्योंकि ऋण संबंधी ये संवितरण पहले 325000 करोड़ रुपए के थे, जो इस वर्ष में बढ़कर 40,000 करोड़ रुपए (लगभग), के हो गए हैं।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई,

2014

इसके अतिरिक्त, हमारे पास 1.56 लाख करोड़ रु पए की बकाया ऋण मंजूरियां हैं, जो वित्त वर्ष 2013-14 में किए गए

संवितरणों के तीन गुने से अधिक हैं। यह इस बात की द्योतक है कि हमारे व्यवसाय की मज़बूत पाइप लाइन आगे की ओर अग्रसर हो रही है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र में नई सरकार बनने के परिणामस्वरूप, बाजार यह अपेक्षा कर रहे हैं कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आधारिक संरचना को काफी महत्व

दिया जाएगा। इससे हमें अपने व्यवसाय के विकास को और अधिक समुन्नत करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र के एक मुख्य खिलाड़ी हैं और विद्युत क्षेत्र के पास ही आर्थिक विकास की कुंजी है।

इस वर्ष हमारे व्यावसायिक निष्पादन की कई उल्लेखनीय उपलब्धियां भी रही हैं। अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की सफलता उन उल्लेखनीय उपलब्धियों में एक है। आपको यह विदित हो कि विकासकर्ताओं के मामलों को संबोधित करने और पहले निर्धारित की

गई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के अनुभव से सीख लेने के बाद, सरकार ने केस -2 की बोली के संबंध में नए मॉडल बोली दस्तावेज प्रकाशित किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आया था, वह यह था कि हमें ईंधन के संकट से गुजरना पड़ा था।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड ने एक नोडल एजेंसी होने के नाते दो अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं की बोली का संचालन किया था। इनमें एक अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की बोली का संचालन ओडीशा में किया गया था और दूसरी अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना की बोली का संचालन 5 वर्ष के अंतराल के बाद चेम्मुर, तमिलनाडु में किया

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

गया था इन मॉडल बोली दस्तावेजों के आधार पर, हमें एक जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। हमें आर.एफ.क्यू. के चरण में, ओडीशा के संबंध में नौ और चेम्मुर के संबंध में आठ आवेदन प्राप्त हुए हैं, और प्रत्येक अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के संबंध में पांच आरपीएफ की दर से कुल दस आरएफपी खरीदे हैं, वे सब के सब अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित बोलीदाता हैं और वे सभी अदानी, जिंदल, स्टरलाइट, जी.एम.आर., एन.टी.पी.सी., एन.एच.पीसी., आदि जैसे विद्युत क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी हैं।

हमारी दो पूर्ण स्वामित्वाधीन नियंत्रित कंपनियों के वाणिज्यिक प्रचालनों का ठोकर-चालन किक-स्टार्ट इस वर्ष की एक दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जैसाकि हमने आपको पिछले वर्ष अवगत कराया था, हमने अपनी इन पूर्ण स्वामित्वाधीन नियंत्रित कंपनियों को अपने प्रयासों से उन्नत किया है। हमारी इन पूर्णस्वामित्वाधीन नियंत्रित कंपनियों में एक है- पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड की

पूंजी परामर्शदात्री सेवाएं, जो ऋण सिंडिकेशन के व्यवसाय को अपने अधिकार में करने का प्रयास करती है। वित्त वर्ष 2013-14 में, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड की पूंजी परामर्शदात्री सेवाओं ने 5300 मेगावाट क्षमतावाली सात पावर परियोजनाओं के संबंध में 5,000 करोड़ रुपए के ऋण सिंडिकेशन व्यवसाय को अपने अधिकार में लिया है।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड की एक दूसरी पूर्ण स्वामित्वाधीन नियंत्रित कंपनी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, जिसकी स्थापना ऊर्जा परियोजनाओं के नवीकरण के निधिपोषण

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हमारी इस नियंत्रित कंपनी ने 300 करोड़ रुपए की ऋण मंजूरी और 25 करोड़ रुपए के ऋण संवितरण के साथ अपने ऋण संबंधी कार्य प्रारंभ कर दिए हैं।

हमारी दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि हम वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, जिनका उल्लेख उस समझौता ज्ञापन में किया गया है, जिस पर हमने भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर किए थे और हमने उन सभी लक्ष्यों को तीन वर्ष के अंतराल के बाद प्राप्त कर लिया है। इस उपलब्धि से हम उन सभी में शीर्ष स्थान के अधिकारी होंगे, जिन्होंने इस समझौता ज्ञापन में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया है। अब मैं आपको विद्युत क्षेत्र में हुए सकारात्मक विकासों के बारे में अवगत कराना चाहूंगा।

क्षमता बढ़ाए जाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। 10वीं योजना में लगभग 21 मेगावाट की क्षमता बढ़ाईं गई थी, जो 10वीं योजना में बढ़ाई क्षमता की 2.5 गुनी है। 12वीं योजना के पहले दो वर्षों में, हमने देखा है कि 38.5 ग्राम वाट की क्षमता बढ़ाई गई है, जो कि 12वीं योजना के कुल लक्ष्य 88 ग्राम वाट की 43 प्रतिशत है

और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 12वीं योजना के दौरान अब तक बढ़ाई गई इस क्षमता की 60 प्रतिशत बिजली का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किया गया है।

ग़ैर-सरकारी सहभागिता की सुविधा के लिए, भारत सरकार ने बिजली की प्रतिस्पर्धी बोली प्राप्त करने की सुविधा के लिए मॉडल बोली दस्तावेज प्रकाशित किए हैं, जिससे कि

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

दीर्घकालिक, मध्यकालिक और अधिकतम शक्ति के आधार पर बिजली की खरीद की जा सके।

जहां तक नवीकरणीय ऊर्जा का संबंध है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सन् 2020 तक 20,000 मेगावाट की सौर क्षमता प्राप्त करने के सरकारी लक्ष्यों के भाग के रूप में, राजस्थान, गुजरात,

लद्दाख और कारगिल में 4000 मेगावाट की सौर अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं स्थापित करने की योजना बनाई है।

जहां तक ईंधन से संबंधित मामलों का संबंध है, बिजली के उपयोगों के आधार पर कोयले की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है, अर्थात् वित्त वर्ष 2013-14 में कोयले की खपत में बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले वर्ष में 455 मीटरी टन कोयले की खपत हुई थी, जिसकी तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 488 मीटरीटन कोयले की खपत हुई है। जहां तक मार्च, 2015 तक प्रारंभ की जानेवाली या मार्च, 2015 तक प्रारंभ किए जाने की संभावनावाली परियोजनाओं के ईंधन की आपूर्ति से संबंधित करारों का संबंध है, जिन परियोजनाओं की संपूर्ण क्षमता लगभग 78000 मेगावाट है, उन सभी के ईंधन की आपूर्ति से संबंधित क़रारों पर हस्ताक्षर पहले ही किए जा चुके हैं और उनके ईंधन की आपूर्ति से संबंधित वे क़रार पहले ही किए जा चुके हैं।

आयातित कोयले पर आधारित परियोजनाओं के संबंध में, सरकार ने ईंधन के संकट को स्वीकार किया है, अर्थात् आयातित कोयले की उच्चतर लागत को ध्यान में रखते

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

हुए,सरकार ने विद्युत परियोजना क़रार में कोयले के संकट का उल्लेख किया है। सी.ई.आर.सी. ने टाटा पावर और अदानी पावर को प्रतिपूरक टैरिफ का भुगतान किए जाने

का निर्णय किया है और इसका आयातित कोयले पर आधारित परियोजनाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सी.ई.आर.सी. के इस निर्णय को ए.पी.टी.ई.एल. के स्तर पर चुनौती दी जा रही है, तो भी यह सही दिशा में उठाया गया एक क़दम है। विद्युत क्षेत्र में पारदर्शकता लाने और उसका दक्षता बढ़ाए जाने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया गया है और उसके माध्यम से कोयले का स्वतंत्र

रूप से विनियमन किए जाने की व्यवस्था की गई है। जहां तक गैस से संबंधित मामले का संबंध है, इस विषय में कई प्रस्ताव किए गए हैं, जिनमें से कुछेक प्रस्तावों पर विचार भी किया जा रहा है, किंतु गैस से संबंधित मामले का समाधान करते हुए ठोर उपायों की घोषणा किया जाना अभी बाकी है। दिसंबर 2013, में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं की पर्यावरण संबंधी अनुमति को आबंटित कोयला ब्लॉक की पर्यावरण एवं वन संबंधी अनुमति से अलग कर दिया है, बशर्ते कि वह आबंटित कोयला ब्लॉक निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत न आए।

जहां तक वितरण क्षेत्र का संबंध है, सभी राज्यों ने वित्त वर्ष 2012-13 के संबंध में टैरिफ आदेश जारी किए थे। लगभग सभी राज्यों ने वित्त वर्ष 2013-14 के संबंध में टैरिफ आदेश जारी करने वाले इन राज्यों में, आंध्रप्रदेश ने टैरिफ़ में 23 प्रतिशत, हरियाणा ने

13 प्रतिशत, राजस्थान ने 11 प्रतिशत तक की वृद्धि की है, आदि। इसलिए, यह इस दिशा में

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई,

2014

उठाया गया एक सकारात्मक क़दम है कि पिछले दो वर्षों में, राज्यों द्वारा टैरिफ़ में संशोधन नियमित रूप से किया जा रहा है। जहां तक वित्त वर्ष 2014-15 का संबंध है, कुल 29 राज्यों में से 7 राज्यों ने टैरिफ़ में अधिकतम 8 प्रतिशत तक की वृद्धि करते हुए वित्त वर्ष 2014-15 के संबंध में टैरिफ़ आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं। इसके अलावा, 11 राज्यों ने टैरिफ़ में अधिकतम 28 प्रतिशत तक की वृद्धि किए जाने के संबंध में टैरिफ़ याचिकाएं पहले ही दाखिल कर दी हैं। इसलिए, जहां तक टैरिफ़ में संशोधन किए जाने का संबंध है, आप यह देख सकते हैं कि कुल 29 राज्यों में

से 18 राज्यों ने वित्त वर्ष 2014-15 में टैरिफ में संशोधन किए जाने के संबंध में क़दम पहले ही उठा लिए हैं।

ईंधन संशोधन नीति (एफ.आर.पी.) लागू किए जाने के बाद, ईंधन संशोधन नीति लागू करनेवाले उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और हरियाणा- जैसे राज्यों ने यह देखा है कि उनकी विद्युत आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और नक़दी संबंधी हानियों आदि में कमी आई है आदि । इन राज्यों ने मासिक आधार पर अग्रिम सब्सिडी का भुगतान करना आरंभ कर दिया है, और इसलिए यह उस दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

जहां तक वितरण संबंधी सुधारों से संबंधित अन्य प्रतिष्ठित कार्यक्रम

का संबंध है सूचना प्रौदोगिकी से समर्थित फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के माध्यम से, समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को 15 प्रतिशत से कम के स्तर तक कम किए जाने के संबंध में एक पुनर्गठित

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (रीस्ट्रक्चर्ड ऐक्सेलेरेटिड पावर डवलमेन्ट एवं रिफ़ॉर्म प्रोग्राम) तैयार किया गया है और इस कार्यक्रम में अच्छी प्रगति

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

हो रही है। यह एक बृहत् कार्यक्रम है, जिसका परिव्यय 50 हज़ार करोड़ रुपए है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 11वीं योजना में किया गया था। यह कार्यक्रम अपने जोरों पर है और इसमें संतोषजनक रूप से प्रगति हुई है। वास्तव में, इस कार्यक्रम के भाग-क का संबंध विद्युत के वितरण से संबंधित कार्य में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किए जाने से है। इस कार्यक्रम के इस भाग में लगभग 1400 विषम नगरों को कवर किया गया है, जिनमें से 550 नगरों ने इस परियोजना के भाग-क के संबंध में सफलता पहले ही प्राप्त कर ली है। इसका तात्पर्य यह है कि वितरण ट्रांसफ़ार्मर के स्तर तक की ऊर्जा लेखा

परीक्षा रिपोर्ट एवं वितरण संबंधी डेटा एक बटन क्लिक करते ही डेटा केंद्र पर उपयोग के अनुसार प्राप्त किया जा सकेगा, जिससे ऊर्जा की चोरी एवं उठाईगीरी को रोकने, तकनीकी मामलों का अभिनिर्धारण करने और तकनीकी संवर्धन संबंधी आवश्यकताओं का अभिज्ञान करने के संबंध में सुधारक प्रशासनिक उपाय करने में सहायता मिलेगी और इन सभी मामलों को उस वितरण नेटवर्क के संबंध में उठाया जा सकेगा। बकाया नगरों और पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार से संबंधित संपूर्ण कार्यक्रम अर्थात् भाग-क और भाग-ख को 12वीं योजना के अंत तक पूरा किए जाने के लिए निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के भाग-ख का संबंध विद्युत के वितरण को मज़बूत बनाने वाली उस वास्तविक योजना से है, जो इस परियोजना के भाग-क के परिणाम पर आधारित है।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

दिनांक : 28 मई,

2014

मुझे विश्वास है कि इन सभी सकारात्मक पहलों से विद्युत क्षेत्र के वातावरण में सुधार आएगा और वह आगे की ओर अग्रसर होगा। सबसे महत्वूपर्ण बात यह है कि यह नई सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आधारिक संरचना को संभवत: उच्च प्राथमिकता देगी और वह विद्युत क्षेत्र से जुड़े मामलों का अपेक्षाकृत अधिक तत्परता से समाधान करेगी और यह बात सरकार की इस समन्वित दृष्टिकोंण में भी दिखाई देती है कि एक मंत्री को कोयला, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मंत्रालयों का प्रभारी बनाया गया है। इसिलए, हमें पूरी आशा है कि हम आगे की ओर अग्रसर उन मामलों का समाधान किया जाएगा तथा विद्युत क्षेत्र एक सकारात्मक दिशा में अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर आगे की ओर अग्रसर होगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अब

मैं अपनी सहयोगी सुश्री नलिनी वनजानी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस संबंध में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दें। उसके बाद, प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया जाएगा।

**संचालक:** अब मैं, कार्यपालक निदेशक सुश्री नलिनी वनजानी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस संबंध में प्रस्तुति दें ।

**नलिनी वनजानी** : सभी को नमस्कार। क्यू4 वित्त वर्ष 2013-14 और कि वित्त वर्ष 2013-14 की सभी मुख्य- मुख्य बातों का उल्लेख पावर फाइनेंस कारोर्पेरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के उद्घाटन भाषण में किया गया है और अब मैं, निष्पादन से संबंधित ब्योरों की आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत दूंगी। हम वित्त वर्ष 2012-13 और वित्त वर्ष 2013-14 के आंकड़ों की अपनी बात आरंभ करेंगे।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

जैसा कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा पहले बताया गया है, कंपनी ने 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 5418 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया है, क्योंकि कि वित्त वर्ष 2012-13 में यह निवल लाभ 4,420 करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 में यह निवल लाभ बढ़कर 5418 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन, यदि हम तुलनात्मक लाभ पर नज़र डालें, अर्थात् असाधारण मदों के समायोजनों के बाद हुए लाभ पर दृष्टिपात करें, तो इस लाभ में 31 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इन असाधारण मदों के समायोजनों से संबंधित बयोरे निम्नलिखित स्लाइडों में दर्शाए जाएंगे।

कुल आय में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले यह आय 17,273 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 21,537 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि ब्याज की निवल आय में 34 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले यह वृद्धि 6,308 करोड़ रुपए थी, जो अब

बढ़कर 8,480 करोड़ रुपए हो गई है। कुल आय में 25 प्रतिशत तक की यह वृद्धि मुख्यत: ब्याज की आय में हुई वृद्धि, 18 प्रतिशत तक ऋणसंबंधी परिसंपत्तियों की आय में हुई वृद्धि, 18 प्रतिशत तक ऋण संबंधी परिसंपत्तियों की आय में हुई वृद्धि और 36 आधार बिंदुओं के अनुसार उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण हुई है। वित्त वर्ष 2013-14 के ब्याज की सीमा में 59 आधार बिंदुओं तक की वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले ब्याज की यह सीमा 2.86 प्रतिशत थी, जो वित्त वर्ष 2013-14 में बढ़कर 3.45 प्रतिशत हो गई है।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

संवितरणों में 4 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले इन संवितरणों की राशि 45151 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 47162 करोड़ रुपए हो गई है और दिनांक

31-03-2014 को ऋणसंबंधी परिसंपत्तियां बढ़कर, 1,89,231 करोड़ रुपए हो गई है और इस तरह उनमें पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वर्ष के अंत में निवल राशि 25098 करोड़ रुपए रही है और इस तरह उसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जहांतक इस तिमाही की मुख्य विशेषताओं का संबंध है, निवल लाभ में 9 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले इस निवल लाभ की राश 1,294 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 1,411 करोड़ रुपए हो गई है । लेकिन, यदि हम तुलनात्मक लाभ पर नज़र डालें, अर्थात् असाधारण मदों के समायोजनों के बाद हुए लाभ पर दृष्टिपात करें,तो लाभ की निवल राशि में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है,। कुल आय में 21 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले यह आय 4,670 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 5,636 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि बयाज की निवल आय में 29 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, क्योंकि ब्याज यह निवल आय पहले 1,739 करोड़ रुपए थी, जो अब

बढ़कर 2,243 करोड़ रुपए हो गई है। इस तिमाही के ब्याज की सीमा में तदनुरूप तिमाही की अपेक्षा 51 आधार बिंदुओं तक की वृद्धि हुई है और इस तिमाही के संवितरणों की राशि में 13 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

है, क्योंकि इन संवितरणों की राशि पहले 14,976 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 16935 करोड़ रुपए हो गई है।

अब हम तुलनात्मक लाभ पर आते हैं। वित्त वर्ष 2013-14 का सूचित कर पश्चात लाभ 5,418 करोड़ रुपए है। तथापि, यदि हम पूर्व वर्ष के आंकड़ों से तुलना करें, तो हमें 334 करोड़ रुपए के कर का

समायोजन करने के बाद 337 करोड़ रुपए की राशि की मानक परिसंपत्तियों से संबंधित आकस्मिक व्यय की व्यवस्था और विदेशी मुद्रा के ऋणों से संबंधित विनिमय की हानि को उनमें से अलग करना होगा सीएसआर और पिछले वर्षों के सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रतिदाय की राशि 23 करोड़ रुपए है तथा पुनर्गठित त्वरित विद्युत मंत्रालय द्वारा पहले की गई थी, उनकी राशि 31 करोड़ रुपए है। उपर्युक्त समायोजन करने के बाद, लाभ की राशि 6141 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि को इंगित करती है। इसीप्रकार, इस तिमाही के तुलना किए जाने योग्य लाभ की राशि 1655 करोड़ रुपए है, जो तदनुरूप तिमाही की अपेक्षा 25 प्रतिशत की वृद्धि को इंगित करती है।

अब हम लाभ और हानि लेखा पर आते हैं। इस लाभ और हानि लेखा की कुल आय को पूर्व स्लाइडों में पहले ही सम्मिलित कर लिया

गया है। जहां तक व्यय संबंधी ब्याज का संबंध है,व्यय में 17 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले यह व्यय 10768 करोड़

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

रुपए था, जो अब बढ़कर 12648 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2013-14 की प्रचालन लागत में 145 करोड़ रुपए की तुलना में 231 करोड़ रुपए तक की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्यत: सी.एस.आर. के व्ययों में हुई 17 करोड़ रुपए की वृद्धि के कारण हुई है, क्योंकि पहले सी.एस.आर. के व्ययों की यह राशि 16 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 63 करोड़ रुपए हो गई है और यह वृद्धि मुख्यत: पूर्व दिशानिर्देशों में की गई व्यवस्था से कम विनियोजन किए जाने की तुलना में लाभ और हानि लेखा के प्रभारों से संबंधित दिशानिर्देशों में किए गए परिवर्तनों के कारण हुई है।

इसके अतिरिक्त, इस वर्ष में, पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के व्ययों में 43 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2013-14 में की गई व्यवस्थाओं में 389 करोड़ रुपए तक की वृद्धि की गई है और इसका कारण प्रधानत: यह है कि मानक परिसंपत्तियों की व्यवस्था में 204 करोड़ रुपए तक की वृद्धि की गई है।

इसके अतिरिक्त, इस वर्ष में हमारे पास एक नया अनुत्पादक परिसंपत्ति लेखा था, जिसमें अतिरिक्त व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता थी तथा इस वर्ष हमारे दो अनुत्पादक परिसंपत्ति लेखाओं को 'अवमानक' से 'संदिग्ध' लेखाओं के रूप में डाउनग्रेड किया गया था। इस वर्ष के डी.टी.एल. सहित कर की व्यवस्था 2140 करोड़ रुपए थी।

इस वर्ष के दौरान, कर की व्यवस्था में 593 करोड़ रुपए तक की वृद्धि की गई है, अर्थात् इस वर्ष के दौरान कर की व्यवस्था में, तदनुरूप अवधि में 38 प्रतिशत की वृद्धि की

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

गई है। यह वृद्धि पी.बी.टी. में की गईं 27 प्रतिशत तक की वृद्धि, अधिभार में की गई 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि के कारण कर की व्यवस्था में की गई 94 करोड़

रुपए तक की वृद्धि, व्यवस्थाओं और आकस्मिक व्ययों में की गई 389 करोड़ रुपए तक की वृद्धि,जो कि आयकर अधिनियम के अधीन अनुमत नहीं है, के कारण मुख्यरूप से की गई

है।

यदि आप तिमाही परिणामों को देखें, तो ब्याज संबंधी आय में 19 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शाई गई है, जबकि ब्याज संबंधी व्ययों में

14 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इस तिमाही में प्रचालन संबंधी लागतों और कर संबंधी प्रावधानों में जो वृद्धि हुई है, उसके कारण वही हैं, जिनका उल्लेख वित्तीय वर्ष के संबंध में किया गया है। इसके अलावा, यदि हम दो तिमाहियों में किए गए प्रावधानों की तुलना करें, तो अंतिम तिमाही के दौरान आर.एस. इंडिया के संबंध में 52 करोड़ रुपए के रिवर्सल का प्रावधान किया गया था, जोकि इस वर्ष नहीं किया गया ।

अब हम तुलन पत्र पर आते हैं। दिनांक 31-03-2014 को हमारे तुलन पत्र में 1,94,164 करोड़ रुपए का उल्लेख किया गया है, जिसमें शेयरधारकों की निधियां 14 प्रतिशत हैं और उनकी राशि 27,375 करोड़ रुपए है तथा उधार राशियां 82 प्रतिशत हैं, जिनकी राशि 1,59,215 करोड़ रुपए है। यदि हम परिसंपत्तियों की ओर देखें, तो ऋण

संबंधी परिसंपत्तियां 97 प्रतिशत हैं, जिनकी राशि 1,89,231 करोड़ रुपए है और बकाया परिसंपत्तियां पूरी तरह से उपेक्षा किए जाने योग्य हैं।

अब हम मूल संकेतकों पर आते हैं। मंजूरियों, संवितरणों और बकाया मंजूरियों पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा पहले ही चर्चा कर ली गई है। मैं, अन्य मापदंडों पर चर्चा करना चाहूंगी। वित्त वर्ष 2013-14 के उत्पादन में 36 आधार बिंदु की वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले ये आधार बिंदु 11.94 प्रतिशत थे, जो अब बढ़कर 12.31 प्रतिशत हो गए हैं। यह वृद्धि उस आय को पुन: जोड़ने के कारण मुख्यरूप से हुई है, जिसका अर्जन वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान किया गया है तथा यह वृद्धि उन नए ऋणों के कारण मुख्यरूप से हुई है, जिनका संवितरण ब्याज की किसी उच्चतर दर से किया गया है।

लागत में 23 आधार बिंदुओं की गिरावट आई है, क्योंकि पहले ये आधार बिंदु 9.09 प्रतिशत, जो अब घटकर 8.85 प्रतिशत हो गए हैं, जिसके कारण हम इस वित्त वर्ष के पूर्वार्द्ध में निम्नतर दर पर संसाधनों का विकास कर सके हैं, क्योंकि इस वित्त वर्ष में बाजार की दरें अपेक्षाकृत कम थीं। इसके कारण सीमा में 59 आधार बिंदुओं और एन.आई.एम. में 4.94 प्रतिशत तक 53 आधार बिंदुओं तक की वृद्धि हुई है।

यदि हम तिमाही आंकड़ों पर नज़र डालें, तो हमारा उत्पादन 12.24 प्रतिशत रहा है और इस तिमाही में निधियों की हमारी लागत 8.75 प्रतिशत रही है, क्योंकि ब्याज की सीमा 3.949 प्रतिशत थी, जो कि तदनुरूप तिमाही की अपेक्षा 51 आधार बिंदुओं की वृद्धि होने

का सूचक है। इस तिमाही में ब्याज का हमारा निवल मार्जिन 4.50 प्रतिशत से बढ़कर 4.99 प्रतिशत हो गया है, जोकि 49 आधार बिंदुओं की वृद्धि होने का सूचक है।

वित्त वर्ष 2013-14 की औसत परिसंपत्तियों पर हमारा प्रतिलाभ 2.98 प्रतिशत है। औसत निवल राशि पर हमारे प्रतिलाभ में 143 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है और यह प्रतिलाभ 23.07 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जबकि ऋण ईक्विटी का हमारा अनुपात 6.36 प्रतिशत था।

जहां तक पूंजीगत पर्याप्तता से संबंधित अपेक्षा का संबंध है, हमारी पूंजीगत पर्याप्तता में दिनांक 31.03.2014 को 20.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्योंकि दिनांक 31.03.2013 को हमारी यह पूंजीगत पर्याप्तता 17.64 प्रतिशत थी और इसका कारण मुख्य रूप से यह है कि हमारे गौण ऋणों में वृद्धि हुई है, जिनकी राशि 3,800 करोड़ रुपए है। हमारे पास राज्य सरकार के गारंटीकृत ऋणों और कमीशन प्राप्त

परियोजनाओं के ऋणों की राशि भी अपेक्षाकृत अधिक थी, जिससे हमें अपनी परिसंपत्तियों के जोखिमभार को घटाकर अपने पूंजीगत अनुपात को बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त हुई है। वित्त वर्ष 2013-14 में, हमारा प्रति शेयर उपार्जन 41.04 रुपए है और प्रतिशेयर हमारा बहीमूल्य 190.13 रुपए है।

अब हम मंजूरियों के विवरण पर आते हैं। इस वर्ष में मंजूरियां 60,729 करोड़ रुपए की थीं, जिनमें से 69 प्रतिशत मंजूरियां उत्पादन संबंधी परियोजनाओं के लिए थीं, 5

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

प्रतिशत मंजूरियां पारेषण के लिए थीं, 8 प्रतिशत मंजूरियां वितरण के लिए थीं और 17 प्रतिशत मंजूरियां अन्य कार्यों के लिए थीं। यदि आप मंजूरियों के क्षेत्रवार वितरण पर नज़र डालें, तो 79 प्रतिशत

मंजूरियां राज्य, केंद्र और संयुक्त क्षेत्र के लिए हैं और 21 प्रतिशत मंजूरियां ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के लिए हैं।

47,162 करोड़ रुपए के संवितरणों में से, 67 प्रतिशत संवितरण उत्पादन परियोजनाओं के लिए किए गए थे, 8 प्रतिशत संवितरण पारेषण और वितरण के लिए किए गए थे तथा 25 प्रतिशत संवितरण अन्य कार्यों के लिए किए गए थे। पुन: यदि हम क्षेत्रवार वितरण पर नज़र डालें, तो 76 प्रतिशत वितरण राज्य, केंद्र और संयुक्त क्षेत्र के लिए किए गए हैं और 24 प्रतिशत वितरण ग़ैर-सरकारी सेक्टर के लिए किए गए हैं।

दिनांक 31-03-2014 को बक़ाया मंजूरियां 1,56,390 करोड़ रुपए की है, जिनमें से जो संवितरण पहले ही किए जा चुके हैं, उनमें 46 प्रतिशत संवितरण ऋणों के हैं, जिनकी राशि 71,612 करोड़ रुपए है और 21 प्रतिशत संवितरण उन ऋणों के हैं, जिनकी राशि 32,711

करोड़ रुपए है और जिनमें प्रलेख निष्पादित किए गए हैं और जिनके संवितरण अभी नहीं किए गए हैं।

अब हम ऋण संबंधी परिसंपत्तियों के संघटन पर आते हैं। दिनांक 31.03.2014 को सकल बक़ाया परिसंपत्तियां 1,88,995 करोड़ रुपए की हैं, जिनमें से 77 प्रतिशत परिसंपत्तियों का संबंध उतपादन संबंधी परियोजनाओं से है, 6 प्रतिशत बक़ाया परिसंपत्तियों

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

का संबंध पारेषण से है, 4 प्रतिशत बक़ाया परिसंपत्तियों का संबंध वितरण से है और 13 प्रतिशत परिसंपत्तियां अन्य श्रेणी की हैं। यदि हम पुन: उधारकर्ताओं के क्षेत्रवार वितरण

पर आएं, तो 50 प्रतिशत ऋण राज्य, केंद्र और संयुक्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं से बक़ाया हैं और 15 प्रतिशत ऋण गैर-सरकारी क्षेत्र के उधारकर्ताओं से बक़ाया हैं।

अब हम परिसंपत्तियों की गुणता पर आते हैं। हमने परिसंपत्तियों की गुणता उत्तम बनाए रखी है। दिनांक 31.03.2014 को हमारी सकल अनुतपादक परिसंपत्तियों का स्तर 0.65 प्रतिशत था और निवल अनुत्पादक परिसंपत्तियां 0.52 प्रतिशत थीं। दिनांक 31.03.2014 को हमारे पास अनुत्पादक परिसंपत्तियों की व्यवस्था 242 करोड़ रुपए की है, मानक परिसंपत्तियों की व्यवस्था 469 करोड़ रुपए की है और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का रिज़र्व 1,730 करोड़ रुपए का है।

अब हम उधार संबंधी संक्षिप्त विवरण पर आते हैं। दिनांक 31.03.2014 को कुल उधार 1,59,215 करोड़ रुपए के थे, जिनमें से बंध-पत्रों की राशि 80 प्रतिशत है,सावधिऋणों की राशि 19 प्रतिशत है, और अल्पावधि ऋणों की राशि 1 प्रतिशत है। यदि आप उधारों के मुद्रावार संघटन को देखें, तो रुपया ऋण कुल उधारों के 94 प्रतिशत हैं और विदेशी मुद्रा ऋण कुल उधारों के 6 प्रतिशत हैं।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

यदि हम स्रोत संबंधी संक्षिप्त विवरण पर नज़र डालें, तो हमारी नियोजित

15 प्रतिशत निधियां ईक्विटी शेयरधारकों से प्राप्त हुई हैं और हमारी परिनियोजित 85 प्रतिशत निधियां विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और मुद्रा बाजारों के उधारों के रूप में है।

राज्य, केंद्र और संयुक्त क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2013-14 में मंजूर किए गए कुछेक ऋणों में, आंध्रप्रदेश की विद्युत उत्पादन कंपनी, भूपालपल्ली को 4,555 करोड़ रुपए, रामगुंडम संयंत्र को 3,746 करोड़ रुपए, सतपुड़ा संयंत्र को 3,720 करोड़ रुपए, तमिलनाडु परिवर्तनशील ऋण के लिए 2,843 करोड़ रुपए, जी.एस..पी. पाइप

पावर कंपनी लिमिटेड को 2,394 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए गए हैं तथा ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के कुछेक मुख्य ऋणों में, 850 मेगावाट की जी.वी. के. रैटल परियोजना के लिए 2500 करोड़ रुपए और इसी परियोजना की हामीदारी (ंअंडरराइटिंग) के लिए 2206 रुपए, कर्चम वैंगटू के अतिरिक्त ऋण के लिए 1,500 करोड़ रुपए और टूटीकोरिन परियोजना के लिए 1,142 करोड़ रुपए के ऋणों की मंजूरियां प्रदान की गइ हैं।

शेयरधारण का पैटर्न इस प्रकार है: दिनांक 31-03-2014 को भारत सरकार 72-80 प्रतिशत की शेयरधारक है। अन्य मुख्य शेयरधारकों में, विदेशी सांस्थानिक निवेशकों के पास 11.17 प्रतिशत और भारतीय वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों के पास 7.92 प्रतिशत शेयर हैं।

जैसाकि पहले बताया गया है, हमने वित्त वर्ष 2013-14 की मंजूरियों और वित्त वर्ष 2014-15 के मूल निष्पादन लक्ष्यों को नीचे दिए अनुसार पार कर लिया है : मंजूरियां

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

55,000 करोड़ रुपए, संवितरण 44000 करोड़ रुपए और संसाधनों को जुटाना 44,000 करोड़ रुपए।

इसी के साथ मेरी संक्षिप्त प्रस्तुति यहां समाप्त होती है। अब निवेशकों के प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया जाएगा।

**संचालक:** अब हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, कृपया प्रश्न करें।

**खंडवाल:** हमारी आय पिछले वर्ष की आय से अधिक है, किंतु हम मूल्यह्रास पिछले वर्ष से थोड़ा कम क्यों दर्शा रहे हैं ?

**आर. नागराजन:** हमने 0.25 प्रतिशत की दर से मानक परिसंपत्तियों की व्यवस्था स्वीकृत तारीख से एक वर्ष पहले ही कर ली है। पुनर्गठित

परिसंपत्तियों की व्यवस्था के संबंध में, हमें यह स्पष्ट नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र हम पर लागू होता है या नहीं और इसलिए हमने इस मामले को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ उठाया है। हमारे पास भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष-2000 के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रतिमान पहले से ही मौजूद है। इन अनुमोदित प्रतिमानों के अनुसार ऋण के पुनर्गठन पर सी.ओ.डी. के पहले एकबार, सी.ओ.डी. के बाद एकबार और उसके अनुत्पादक परिसंपत्ति हो जाने के बाद एकबार विचार किया जा रहा है। यदि हम विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रतिमानों और ाारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिमानों का सम्मिलित करें, तो हमारी बहियों में भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ऋण के पुनर्गठन पर अवधि के आधार पर विचार कर रहा है, इसलिए हमने इस मामले को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ उठाया है और इस मामले का

समर्थन विद्युत मंत्रालय ने भी किया है। आशा है कि हमें भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुकूल उत्तर प्राप्त होगा। इसलिए, हम इन प्रतिमानों के अनुसार व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।

**पुनीत**: देव कैपीटल मार्केट्स से मैं, पुनीत परिवर्तनशील ऋणों से संबंधित औसत उत्पादन के विषय में अपना पहला प्रश्न करना चाहता हूं। कृपया पिछले वर्ष के परिवर्तनशील ऋणों से संबंधित औसत उत्पादन के बारे में बताएं।

**आर.नागराजन:** सभी ऋण 12-.25 प्रतिशत की दर से मंजूर किए जाते हैं और राज्य सरकार की गारंटी से समर्थित होते हैं।

**पुनीत**: इस तिमाही के दौरान एक लेखा स्लपेज के बारे में उल्लेख किया गया था। उस स्लिपेज का उल्लेख किन कारणों से किया गया था

**<u>आर.नागराजन</u>**: आंध्रप्रदेश में 77 करोड़ रुपए मात्र की आयातित कोयले पर आधारित एक परियोजना है। वास्तव में, उधारकर्ता ठीक-ठीक काम कर रहा था, किंतु ई.पी.सी. के ठेकेदार के साथ उसकी एक समस्या थी, जिसके परिणामस्वरूप उससे बैंक गारंटी मांगी गई थी। पहली बात तो यह है कि उधारकर्ता के खाते में अभी 11 करोड़ रुपए हैं और यदि हम इस धनराशि को विनियोजित करें, तो उसका खाता अनुत्पादक परिसंपत्ति की श्रेणी में नहीं आ सकता। लेकिन, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह परियोजना पूरी हो। दूसरी बात यह है कि हमें पी.टी.सी. ने दिलासा दी है, जोकि इस परियोजना के ईक्विटी भागीदारों में एक है। इसमें प्रमोटर की ईक्विटी 51 प्रतिशत है और पी.टी.सी. की ईक्विटी 49 प्रतिशत है। हम

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

ई.पी.सी. की इस समस्या के निपटान के संबंध में, ई.पी.सी. के ठेकेदार, पी.ओ.सी. और उधारकर्ता के साथ विचार -विमर्श कर रहे हैं।

**पुनीत**: हां, यह वास्तव में एक छोटा-सा लेखा है। इसलिए, मैं देयता संबंधी पक्ष के विषय में एक बात और जानना चाहता हूं और वह यह है कि आपकी समस्त देयता में से कितनी देयता अब अस्थिर (फ्लोटिंग) है? वास्तव में, जहां एक ओर आप अपनी 'परिसंपत्ति और देयता का प्रबंध करें' की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आपके अधिकतर ऋण तीन वर्ष के रिसेटवाले हैं, और दूसरी ओर आप कम से कम उस भाग की लगभग 30 प्रतिशत की देयता के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं, इसलिए, क्या आप अभी भी उस प्रक्रिया का पलान कर रहे हैं और उस संबंध में आपकी कितनी देयताएं अस्थिर हैं?

**आर.नागराजन**: दिनांक 31-3-2014 को अचल देयताएं 78 प्रतिशत हैं और अस्थिर देयताएं 22 प्रतिशत हैं। जहां तक परिसंपत्ति संबंधी पक्ष का जहांतक संबंध है, स्थिर दर वाली परिसंपत्तियां 98 प्रतिशत हैं।

प्रत्येक तीन वर्ष में पुन: जोड़ी जाने जानेवाली परिसंपत्तियां लगभग 94 प्रतिशत हैं।

**पुनीत**: अंतिम प्रश्न, क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश अद्यतन किया गया है?

**आर.नागराजन:** हम इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्युत मंत्रालय द्वारा समर्थित प्रतिमानों का पालन कर रहे हैं। आशा है कि इस संबंध में जून तक कोई समाचार प्राप्त होगा।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

**एम. के.गोयल**: हमें पूरी उम्मीद है कि यदि हम पूर्व मामलों की तरह इस मामले को भी भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ उठाएंगे और उसका औचित्य सिद्ध करेंगे, तो हम इसका कोई विशेष प्रबंध कर सकेंगे।

**मनीष**: डच बैंक से मैं, मनीष आपसे उन आंतरिक प्रतिमानों के विषय में अपना पहला प्रश्न करना चाहता हूं, जिनका आप पालन करते हैं। आपकी पुनर्गठित बही और पुनर्निर्धारित बही का विवरण क्या है?

**आर.नागराजन:** डी.सी.सी.ओ. के बिलंब का पुनर्निर्धारण लगभग 9,665 करोड़ रुपए है और जिन मामलों में चुकौती कर दी गई है और उसके बाद हमने उन्हें पुनर्गठन कर लिया है, उनमें पुनर्निर्धारण 1,835 करोड़ रु पए है। गैर - सरकारी क्षेत्र के मामले में कुलयोग लगभग 11,500 करोड़ रुपए है।

**मनीष**: क्या यह सभी ग़ैर - सरकारी क्षेत्र में है?

**आर.नागराजन:** हां, यह सभी ग़ैर - सरकारी क्षेत्र में हैं।

**मनीष** : क्या ये प्रतिमान आपकी राज्यसरकार की प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होते हैं?

**आर.नागराजन:** विद्युत मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित प्रतिमानों के अनुसार,ये प्रतिमान राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होते हैं।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

**मनीष :** महोदय, दूसरी बात यह है कि आपके गैस-आधारित परियोजनाओं के संबंध में आपकी नीति क्या हैं?

**एम. के. गोयल:** ये हमारी कुल ऋण बही के 3 प्रतिशत मात्र हैं और जहां तक ग़ैर-सरकारी क्षेत्र का संबंध है, ये हमारी कुल ऋण बही के 0.6 प्रतिशत मात्र हैं।

**मनीष :** मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि ऋणों के रूप में आपके ग़ैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और कितनी परियोजनाओं का अभी निर्माण किया जाना है?

**आर.नागराजन:** ग़ैर-सरकारी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन योजना की 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में से चालू की गई परियोजनाएं 6,670 करोड़

रुपए की हैं और शेष परियोजनाओं को अभी चालू किया जाना है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए की हैं। ऋण बही के एक समग्र आधार पर, 28 प्रतिशत परियोजनाएं चालू की गई हैं, अर्थात् लगभग 52,747 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चालू की गई हैं और शेष परियोजनाओं को अभी चालू किया जाना है।

**<u>अंकित :</u>** सी.आर.आई.एस.आई.एल. से मैं, अंकित प्रश्न करना चाहता हूं। आपने कहा है कि आपको भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण प्रतिमानों से छूट प्राप्त है। महोदय, यदि आप उन प्रतिमानों का पालन करेंगे, तो उसका क्या प्रभाव होगा, और यदि आपको उन प्रतिमानों का पालन वास्तव में किए जाने के लिए कहा जाएगा, तो लाभ और हानि लेखा पर उसका क्या प्रभाव होगा?

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

**आर.नागराजन:** जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिमानों में दो वर्ष की समयावधि की बात कही गई है, जबकि हम दो बार की पुनर्गठन प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। इसलिए, यह हमारे लिए एक समस्या होगी।

**अंकित :** महोदय, क्या आप हमें अपनी अनुत्पादक परिसंपत्तियों की परियोजनाओं की स्थिति और कुछेक उन प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति के बारे में बताएंगे, जो आपकी अनुत्पादक परिसंपत्तियों से संबंधित हैं और उस बारे में उनकी प्रस्थिति क्या है?

**आर.नागराजन:** पहली परियोजना है- ओम शक्ति एनर्जी, जो लगभग 9 करोड़ रुपए की है। इस मामले में हमने एक मुकद्दमा दायर किया है और हमने उसके लिए पूरा प्रावधान कर लिया है। कोण सीमा गैस एंड पावर लिमिटेड के मामले में, हमने लगभग 400 करोड़ रुपए के ऋण की तुलना में 20 प्रतिशत राशि का प्रावधान कर लिया है और हमने आई.डी.बी.आई. बैंक के साथ उसका पुनर्गठन कर लिया है। आशा है

कि अप्रैल, 2014 से उन्हें गैस प्राप्त होने लगेगी। लेकिन, आज वे भी उपेक्षित स्थिति में है। उसके बाद, एक दूसरा लेखा महेश्वर हाइडल पावर लिमिटेड का है, जो अब तक की सबसे बड़ी अनुत्पादक परिसंपत्ति है। 400 करोड़ रुपए के ग़ैर - निधि - आधारित परियोजना के साथ- साथ लगभग 700 करोड़ रुपए की परियोजना है। हम, मध्यप्रदेश सरकार से धनराशि प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समर्थित हैं, किंतु हम अभी भी पूरी धनराशि प्राप्त नहीं कर पारहे हैं और इसलिए हम यह अनुरोध कर रहे हैं कि उसका प्रभार किन्हीं अन्य सरकारी कंपनियों

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

को सौंप दिया जाए। अभी इस संबंध में बातचीत की जानी है और आ कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। आशा है कि यह कार्य सितंबर

के अंत तक अवश्य हो जाएगा। एक अन्य लेखा एमपी पावर कंपनी का है, जिसमें 27 करोड़ रुपए की परियोजना है। इस कंपनी

का कुछ पुराना बाकी (अतिदेय) है और इस बात की संभावना है कि हम इस लेखा को अद्यतन कर सकेंगे। कृष्णा - गोदावरी पावर लिमिटेड के मामले में, ऋण लगभग 77 करोड़ रुपए का है। जैसाकि मैंने पहले बताया है, हम पी.टी.सी. और प्रमोटर के साथ विचार - विमर्श कर रहे हैं, ताकि इस मामले का समाधान किया जा सके। कोण सीमा गैस एंड पावर लिमिटेड और महेश्वर हाइडल पावर लिमिटेड के मामले में, हमने 20 प्रतिशत राशि का प्रावधान पहले ही कर लिया है। ओम शक्ति एनर्जी के मामले में, 100 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है तथा कृष्णा - गोदावरी पावर लिमिटेड और एमपी पावर लिमिटेड के मामले में 10 प्रतिशत राशि का प्राविधान किया गया है ।

**<u>उमंग</u>:** सी. आई. एम.बी. से मैं उमंग कुछेक प्रश्न करना चाहता हूं। आपके ऋणों और उधारों के किस अनुपात का पुन: मूल्य निर्धारण वित्त वर्ष 2013-14 में किया जा रहा है?

**<u>आर.नागराजन</u>:** वित्त वर्ष 2014-15 में, जिन परिसंपत्तियों का पुन: मूल्यनिर्धारण किया जा रहा है, वे लगभग 46,000 करोड़ रुपए की हैं और जिन देयताओं का पुन: मूल्यनिर्धारण किया जा रहा है, वे लगभग 33 करोड़ रुपए की हैं।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

**<u>उमंग</u>:** ठीक है। चौथी तिमाही में हमने लगभग प्रतिशत के मार्जिन देख हैं, जो संभवत हमारे लिए उच्चतम मार्जिन है। इस प्रकार की आगामी ट्रज़क्टरी__को बनाए रखने के विषय में आप कितने आश्वस्त हैं?

**आर.नागराजन:** वास्तव में, हम भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जैसाकि आई.पी.ओ. और एफ.पी.ओ. में आपको बताया है, पिछले निष्पादन के आधार पर, हम 2 प्रतिशत मात्र की सीमा बनाए रखने का प्रयास करेंगे,लेकिन हम इससे उच्च स्तर बनाए रखे हुए हैं। इसीप्रकार हम यह भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि मार्जिन हमेशा 5 प्रतिशत का ही रहेगा। लेकिन, हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हम एन.आई.एन. 4.75 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के बीच बनाए रखें।

**उमंग:** महोदय, मैं, पुनर्गठित ऋणों के विषय में दो स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं । आपने यह उल्लेख किया है कि पुनर्गठित ऋण गैर-सरकारी सेक्टर में लगभग 11,500 करोड़ रुपए के हैं। अत:, आंतरिक रूप से वह प्रक्रिया क्या है या आंतरिक रूप से वे प्रतिमान क्या हैं, जिनके आधार पर राज्य या केंद्रीय सरकार के ऋण पुनर्गठित किए

जाते हैं या उन्हें पुनः निर्धारित किया जाता है और उनकी राशि क्या होती है?

**आर.नागराजन:** एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है, चाहे व्यवस्था की गई हो या नहीं की गई हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो भी पुनर्गठित करते हैं, उसके किसी भी मामले में कोई त्याग नहीं किया जाता है, क्योंकि डी.सी.सी.ओ. में परिवर्तन हो जाता है।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

**एम.के.गोयल :** जहां तक सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का संबंध है, हम जो भी पुनर्गठन करते हैं, वह केवल डी.सी.सी.ओ. के आस्थगन के संबंध में ही होता है। सामान्यतः, ऐसे कोई मामले नहीं होते हैं, जिनमें चुकौती आरंभ हो गई हो और उनमें कोई व्यतिक्रम रहे।

**उमंग:** जहां तक ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के ऋणों का संबंध है, मामले की प्रकृति के आधार पर कुछ त्याग किया जासकता है।

**आर.नागराजन:** वर्ष 2007 में, हमारे बोर्ड ने यह निर्णय किया है कि ऋण के जिस मामले में हमने पुनर्गठन इस कारण किया है कि लेखा अनुत्पादक परिसंपत्ति बन गया है, उसमें भी हम उधारकर्ता के प्रति एक रुपए का भी त्याग नहीं कर सकते। अन्य बैंकों की प्रक्रिया के अनुसार, बैंकों के साथ-साथ हमने भी ऋणअवधि की दर कम कर दी है। लेकिन, उस ऋणअवधि के समाप्त हो जाने के बाद, हम बक़ाया ब्याज की वसूली कर रहे हैं। माना कि ब्याज की हमारी दर 15.0 प्रतिशत है। यदि अन्य बैंकों की ऋणअवधि 12 वर्ष है, तो हम 12 वर्ष तक अन्य बैंकों की तरह 11 प्रतिशत ब्याज प्रभारित करते हैं और 12 वर्ष की अवधि के बाद हम 15.0 प्रतिशत की ब्याज के साथ शेष 4 प्रतिशत ब्याज की वसूली करते हैं।

**उमंग:** ठीक है। अब मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक हमें ये पुनर्गठित या पुनर्निर्धारित ऋण प्रदान करने के लिए कहेगा,

तो मेरा अनुमान है कि वह 5 प्रतिशत होगा और जो भी त्याग करना होगा, वह उससे अधिक होगा।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

**<u>आर.नागराजन</u>:** अपने पहले उत्तर में मैंने यह कहा है कि इससे हमें समस्या होगी। सरकारी क्षेत्र के उधारकर्ता के मामले में, हमें ऋण उन आरंभिक चरणों में प्राप्त हो रहा है,जिनमें ऋण चालू किए जाने की तारीख़ का उल्लेख करते हुए केवल डी.पी.आर. तैयार की जाती है। राज्य सरकार 4 वर्ष के बाद ही अनुमोदन प्रदान करती है। मूल डी.सी.सी.ओ. उस समय तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद ही वे हमें प्रलेखन, गारंटी और संवितरण के लिए प्राप्त होते हैं।

मंजूरी की तारीख, प्रलेखन, गारंटी और संवितरण के बीच समय का अंतराल होता है। इसलिए, यही कारण है कि हमने भारतीय रिज़र्व

बैंक से यह अनुरोध किया है कि वह हमें कम से कम 5 वर्ष का समय दे, जिससे कि हम भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिमानों के अनुरूप कार्य कर सकें। हमें राज्य सरकार की सत्ताओं को भी अपने समकक्ष लाना होगा।

पहले, लेLाा 5 वर्ष तक लंबित रहते थे, किंतु अब लेखा प्रयासपूर्वक यथासमय के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इसलिए, हमें यहां भी राज्यसरकार की सत्ताओं को इसी प्रकार से बढ़ावा देना होगा, जिससे कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिमानों के अनुरूप कार्य कर सकें।

**<u>उमंग</u>:** निश्चय ही, इससे हमारे पास इन ऋणों के संबंध में एक मानक परिसंपत्ति संबंधी प्रावधान हो जाएगा, अर्थात् इससे हमारे पास 25 आधार बिंदु हो जाएंगे।

**<u>आर.नागराजन</u>:** हां, हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिमानों के अनुसार बक़ाया परिसंपत्तियों का प्रावधान0.25 प्रतिशत की दर से दिनांक 31.03.2014 को पहले ही कर लिया है।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई, 2014

**दिगंत** एन्टीक से मैं, दिगंत यह अनुरोध करता हूं कि एफ.आर.पी. को लेकर जो हो रहा है, उसके बारे में संक्षेप में जानकारी प्रदान की जाए, क्योंकि आप उसकी नई मंजूरियों, संवितरणों और राज्यों के निष्पादनों के बारे में जानते हैं और क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों ने इन राज्यों को उधार देना आरंभ कर दिया है?

**आर.नागराजन:** चार राज्यों- उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान ने एफ.आर.पी. योजना में सहभागिता की है। इससे तमिलनाडु में विद्युत आपूर्ति में सुधार आया है। उत्तर प्रदेश भी वित्त वर्ष 2014-15 के संबंध में टैरिफ़ याचिका दाखिल कर रहा होगा और टैरिफ़ बढ़ाए जाने की मांग कर रहा होगा। जहां तक राजस्थान और हरियाणा का संबंध है, उन्होंने एफ.आर.पी. योजना के अधीन मंजूर की गई पूरी राशि पर आहरित नहीं की है, जो इस बात को इंगित करती है कि उनकी

स्थिति में सुधार आया है। बैंक उधार देने के लिए तैयार हैं और यही कारण है कि वे उस एफ़.आर.पी. के लिए पी.एफ़.सी. से धन नहीं लेना चाहते, जिसकी मंजूरी हमने प्रदान की है। हमने हरियाणा और राजस्थान के लिए जो ऋण मंजूर किए हैं, उनमें से हरियाणा ने लगभग 800 करोड़ रुपए प्राप्त नहीं किए हैं और राजस्थान ने उनमें से लगभग 1700 करोड़ रुपए प्राप्त नहीं किए हैं। चालू वर्ष की टैरिफ़ वृद्धि के बारे में

श्री चतुर्वेदी द्वारा की गई समीक्षा के संबंध में बैठक में चर्चा की गई थी। उस समय, हमें यह बताया गया है कि चुनाव संबंधी कार्य समाप्त होने के बाद, सभी राज्यों के विनियामक आयोगों की 16वें बैठक द्वारा टैरिफ में वृद्धि की जाएगी। ऐसे राज्य अर्थात् झारखंड, बिहार

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

दिनांक : 28 मई,

2014

और आंध्रप्रदेश किसी संस्था से कार्य निधि नहीं लेना चाहते हैं, जिनके संबंध में वर्ष 2014 में एफ.आर.पा.ळ योजना के लिए विचार किया गया है। राज्य सरकार उनकी सहायता करने के लिए तैयार है, और इसलिए उनकी इसमें कोई रुचि नहीं है। केवल झारखंड ने हमसे निधिपोषण का अनुरोध किया है और हम उसके लिए 3000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे सकते हैं।

एफ.आर.पी. योजना अभी भी प्रक्रियाधीन है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों ने बैंकों को जारी किए जाने के लिए अपेक्षित 50 प्रतिशत बंध-पत्र पहले ही जारी कर दिए हैं। टैरिफ़ की जो वृद्धि प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक फ़ाइल की जानी अपेक्षित है, उसे

फ़ाइल नहीं किया गया है। चूंकि अब निर्वाचन के परिणाम आ चुके हैं, टैरिफ़ में वृद्धि क्रमश अपेक्षित है।

**दिगंत:** क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों ने इन राज्यों को पुन: उधार देना आरंभ कर दिया **है**?

**आर.नागराजन:** तमिलनाडु, राजस्थान और हरियाणा राज्यों ने निधिपोषण प्राप्त किया है हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य ने निधिपोषण प्राप्त नहीं किया है।

**कुणाल:** इडलवेइस से मैं, कुणाल पुनर्गठन के पक्ष के विषय में जानना चाहता हूं। महोदय, मैं पुनर्गठित परियोजनाओं में से कुछेक पुनर्गठित परियोजनाओं की स्थिति के बारे में आपसे

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई,

2014

जानना चाहता हूं। क्या ऐसी कोई संभावना है कि उनमें से कोई पुनर्गठित परियोजनाएं आगामी 12 से 18 माह के अंतर्गत अनुत्पादक परिसंपत्ति में वास्तव में परिवर्तित हो जाएंगी?

**आर.नागराजन:** पुनर्गठित / पुनर्निर्धारित परिसंपत्तियां 11500 करोड़ रुपए की हैं, जिनमें से कृष्णा- गोदावरी पावर लिमिटेड, महेश्वर हाइड्रल पावन लिमिटेड और कोणसीमा गैस एंड पावर लिमिटेड पहले से ही अनुत्पादक परिसंपत्तियां हैं।

**एम. के. गोयल:** सुजलोन के मामले में, दिसंबर, 2014 के बाद से भुगतान देय है।

**कुणाल:** इसलिए, कोई बड़ी छूट नहीं है?

**एम. के. गोयल:** अनुत्पादक परिसंपत्तियों में आगे और डाउनग्रेड होने की उम्मीद नहीं है।

**कुणाल:** ठीक है। क्या हम किसी पुनर्गठन और अनुत्पादक परिसंपत्ति को लेकर किसी दबाब का अनुभव कर रहे हैं? क्या हम किसी परियोजना के विषय में किसी प्रकार का दबाव, मानक बही के अनुसार, अनुभव कर रहे हैं?

**आर.नागराजन:** मानक बही के अनुसार, हमें अभी किसी परियोजना के अनुत्पादक परिसंपत्ति की श्रेणी में आने की उम्मीद नहीं है। भविष्य में क्या होगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते।

**कुणाल:** महोदय, हमने संवितरणों एवं मंजूरियों के जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उनके बारे में हम समझौता ज्ञापन में काफी अनुदार प्रतीत होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी वह अनुदारता लगभग 44000 करोड़ रुपए के संवितरणों एवं मंजूरियों के रूप में परिलक्षित

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई,

2014

होगी। इसलिए, 1,56,000 करोड़ रुपए का बक़ाया मंजूरियों को ध्यान में रखते हुए, यथार्थपरक आंकड़ा क्या है और ऋण का विकास क्या है, क्योंकि हमने इस वर्ष में संवितरण का 4 प्रतिशत विकास किया है? हमने समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के रूप में

अगले वर्ष के लिए लगभग 1 प्रतिशत या 2 प्रतिशत की अन्य गिरावट होने की संभावना दर्शाई है, जिससे 18 प्रतिशत से कम के विषम ऋण विकास में पुन: मंदन होने की संभावना रहेगी। इसलिए, इस चुनाव के बाद हम इसे कहां देखते हैं? इसलिए,ऋण के विकास के रूप में वह आंकड़ा कौन-सा है, जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया है?

**<u>एम. के. गोयल:</u>** मैं सोचता हूं कि इस समय इसका पूर्वानुमान लगाना एक जल्दबाजी होगी और मैं यह भी सोचता हूं कि इस अवस्था में यह पूर्वानुमान उचित नहीं होगा। निश्चय ही, हम अपने उन लक्ष्य से अधिक प्राप्त करने जा रहे हैं, जिन्हें हमने अपने लिए पहले ही

निर्धारित कर लिया है। हम उन लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बता सकेंगे, तत्काल नहीं।

**एम. के. गोयल:** महोदय, ओ. एन. जी.सी. त्रिपुरा में संपूर्ण पूर्व अदायगी जैसा है, जो कर ली गई है या उन्होंने उसका अभी किया है?

**कुणाल:** महोदय, ओ.एन.जी. सी. त्रिपुरा में संपूर्ण पूर्व अदायगी- जैसा है, जो कार्य कर लिया गया है, उन्होंने उसका भुगतान कर दिया है

**आर.नागराजन:** उसकी जनवरी, 2014 में 2165 करोड़ रुपए की पूर्व अदायगी पूरी तरह से कर दी गई है।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
दिनांक : 28 मई,

2014

**कुणाल:** ठीक है। इसलिए, क्या वह पूर्णत: पुनर्गठन और ऋण बही की सीमा से भी बाहर है?

**आनागराजन** जी, हां।

**एम.के. गोयल:** आशा है कि हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं और आपकी सभी शंकाओं के निवारण कर दिए हैं। आपने सक्रिय सहभागिता के लिए और हमें धैर्यपूर्वक सुनने के लिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया अब हमारे साथ जलपान के लिए चलें। धन्यवाद।

**संचालक:** आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जलपान के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद।

**टिप्पणी:** पठनीयता और सुसंगता में सुधार लाने के लिए, इस दस्तावेज का संपादन कर दिया गया है।